BIHAR FOUNDATION
BONDING • BRANDING • BUSINESS

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

+91 0612 2547371
+91 85442 99526
https:// biharfoundation. bihar.govt.in

सम्प्रति बिहार

बिहार फाउन्डेशन की प्रस्तुति

बिहार के महत्वपूर्ण अखबारों में छपे **सकारात्मक** समाचारों का संकलन

आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी बुधवार विक्रम संवत् 2079। 06 जुलाई 2022

श्रम संसाधन विभाग ने आंकड़ा संकलित करने को बनाया विशेष कोषांग

सूबे में सरकार रोजगार का अध्ययन कराएगी

एक्सक्लूसिव

■ संजय

- आंकड़ा संकलित करने के लिए मान्यता प्राप्त कंपनियों से पत्राचार किया जाएगा
- सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, उद्योग और अन्य विभागों से लिया जाएगा आंकड़ा

पटना। सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में लोगों को मिल रहे रोजगार का राज्य सरकार अध्ययन कराएगी। किस विभाग ने कितनी नौकरी दी, निजी क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका आंकड़ा तैयार होगा। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने एक विशेष कोषांग का गठन किया है।

दरअसल, अभी बिहार में हर साल कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसका वैधानिक आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। श्रम संसाधन विभाग की ओर से लगने वाले नियोजन सह मार्गदर्शन मेला या जॉब कैम्प के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों का ही आंकड़ा सरकार के पास है। जबकि श्रम संसाधन विभाग के अलावा भी सरकार के दूसरे विभागों की ओर से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इसी के आलोक में तय हुआ कि न केवल सरकारी बल्कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार पाने वालों का आंकड़ा एकत्रित किया जाए। बीते दिनों मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रोजगार से संबंधित आंकड़ों को संकलित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग को नोडल बनाया गया। नोडल विभाग के नाते श्रम संसाधन विभाग ने रोजगार का आंकड़ा संकलित करने के लिए एक कोषांग का गठन किया है। विभाग के नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशक को इस कोषांग का अध्यक्ष बनाया गया है। सदस्य के तौर पर नियोजन के संयुक्त निदेशक, पटना प्रमंडल के उप श्रमायुक्त और स्थापना के प्रशाखा पदाधिकारी को शामिल किया गया है। यह कोषांग न केवल श्रम संसाधन बल्कि सामान्य प्रशासन, उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही सरकार के अन्य विभागों के माध्यम से मिलने वाले रोजगार के आंकड़े संकलित करेगा। सरकारी विभागों के अलावा निजी क्षेत्र में मिल रहे रोजगार का आंकड़ा संकलित करने के लिए मान्यता प्राप्त कंपनियों से पत्राचार किया जाएगा। ईएसआईसी, पीएफ कार्यालय से भी रोजगार पाने वालों का आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरविन्द कुमार चौधरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रोजगार सृजन से संबंधित आंकड़ों को संकलित करना ही इस कोषांग का मूल दायित्व होगा।

01 अप्रैल 2020 से आंकड़ा एकत्रित करने का निर्णय लिया गया

कोषांग की जिम्मेवारी होगी कि आंकड़ों में दोहराव न हो

विभाग ने एक अप्रैल 2020 से रोजगार पाने वालों का आंकड़ा एकत्रित करने का निर्णय लिया है। एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 और एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 तक की अवधि में मिले रोजगार के आंकड़े संकलित किए जाएंगे। इसके अलावा एक अप्रैल 2022 के बाद इस वर्ष मिले रोजगार के अद्यतन आंकड़ों को भी संकलित किया जाएगा। कोषांग की यह जिम्मेवारी होगी कि आंकड़ों में दुहराव न हो।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 06.07.2022 | पृष्ठ सं० 04

फैसला: पटना में नया ड्रेनेज सिस्टम बनेगा

कैबिनेट फैसला 1

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। पटना शहर और इसके आसपास के क्षेत्र खगौल, दानापुर और फुलवारीशरीफ जलजमाव से मुक्त होंगे। जलनिकासी की प्रभावी व्यवस्था के लिए इन क्षेत्रों में नया ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। 957 करोड़ रुपये की इस योजना को मंगलवार को स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग की इस योजना को मूर्तरूप देने के लिए पटना शहर को सात और फुलवारीशरीफ, खगौल और दानापुर को दो अर्थात कुल नौ जोन में बांटा गया है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत यह योजना बनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति इस योजना का कार्यान्वयन बुडको के माध्यम से किया जाएगा।

बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस योजना का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा।2019 में पटना के कई इलाकों में जलजमाव हुआ था। इसके बाद राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी अनुशंसा की थी कि पटना शहर में जलनिकासी के लिए व्यापक योजना बननी चाहिए, ताकि लोगों को जलजमाव की समस्या से निजात मिल सके। इसके लिए राज्य वित्त आयोग से एक हजार करोड़ का प्रावधान भी पहले ही कर दिया गया है। इसलिए योजना के तेज गति से क्रियान्वयन में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। अन्य फैसले P09

- सात निश्चय-2 के अंतर्गत पटना के लिए बनी योजना
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 24 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई

राज्य में पांच नये ग्रिड सब-स्टेशन बनेंगे

राज्य में पांच नये ग्रिड सब-स्टेशन बनेंगे। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए पश्चिम चंपारण के बगहा, गया के भोरे और बारावट्टी तथा औरंगाबाद के दाउदनगर में दो 50 एमवीए **2** क्षमता वाली 132/22 केवी ग्रिड सब-स्टेशन व औरंगाबाद के नवीनगर में तीन 50 एमवीए क्षमता वाली 132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन एवं इससे संबंधित संचरण लाइन के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इन योजना का कार्यान्वयन स्पेशन प्लान (बीआरजीएफ) मद में प्राप्त राशि से होगा। 220 केवी व 132 केवी संचरण लाइनों के नवीकरण व आधुनिकीकरण के अंतर्गत तार बदलने आदि कार्य के लिए 498 करोड़ 55 लाख की स्वीकृति दी गई है।

957 करोड़ रुपये खर्च होंगे नए ड्रेनेज सिस्टम पर

विद्युत बोर्ड कर्मियों के बकाया सेवांत लाभ को 757 करोड़

पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का 31 अक्टूबर 2012 तक की **3** अवधि में बकाया (अनफंडेड टर्मिनल दायित्व के विरुद्ध) सेवांत लाभ के लिए कैबिनेट ने 757 करोड़ 63 लाख की स्वीकृति दी है। यह राशि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को तीन किस्तों में उपलब्ध कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत उक्त राशि की स्वीकृति दी गई है।

सुपौल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापित होगा

राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में **4** मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया। साथ ही कैबिनेट ने इसके निर्माण के लिए 603 करोड़ 68 लाख रुपये की स्वीकृति भी दे दी है। चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम, लिमिटेड पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल स्टीमेट के आधार पर उक्त राशि की स्वीकृति दी गई है। इससे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विकास के साथ-साथ राज्य की जनता को गुणवतापूर्ण चिकित्साकीय सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग आगे की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएगा। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 24 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 06.07.2022 | पृष्ठ सं० 1

• कला-संस्कृति, हस्त कला और गांव के वातावरण को देख पायेंगे पर्यटक

ग्रामीण टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, पर्यटन विभाग अगस्त से करेगा गांव का चयन

संवाददाता ▷ पटना

राज्य भर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से कई योजनाएं चल रही है. जिसके माध्यम से पर्यटकों को सुविधाएं दी जाती है. अब विभाग ग्रामीण टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए गांव का चयन करेगी, जहां कला-संस्कृति, हस्त कला और गांव के खान-पान को बढ़ावा दिया जायेगा. इसके लिए विभाग की ओर से जिलों को दिशा -निर्देश भेजा गया है. पर्यटन विभाग इस योजना पर अगस्त से काम तेज करेगा.जिलों से मिली रिपोर्ट के बाद गांव का चयन किया जायेगा.

खान-पान से बढ़ेगा रोजगार : गांव में पर्यटक पहुंचे. इसके लिए गांव का चयन किया जायेगा. जिसमें वैसे जिलों को पहले चुना जायेगा. जहां के खान-पान को पहचान देश भर में हो.वहीं, उस गांव की पहचान कुछ अन्य बातों में भी हो, जिसे देखने की उत्सुकता पर्यटकों को रहे.

पर्यटकों के लिए होंगे सुलभ रास्ते : जिस गांव का चयन किया जायेगा. उस गांव तक पर्यटकों के लिए रास्तों को सुलभ करने के लिए भी काम होगा. वहां पर आने -जाने की पूरी व्यवस्था होगी. साथ ही, ग्रामीण परिवेश में पर्यटक रात में ठहर सकें और गांव के मनमोहक वातावरण में एक-दिन रह सकें. इसकी पूरी व्यवस्था की जायेगी.

गांवों में ढाबा व रेस्टोरेंट से रोजगार

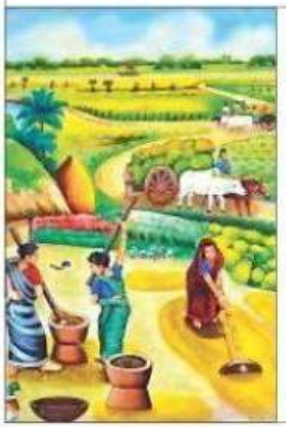

ग्रामीण क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों पर रेस्टोरेंट व ढाबा खोलने पर विभाग ने पूरी प्लानिंग कर ली है. इन सड़कों पर खुलने वाले रेस्टोरेंट से ग्रामीण टूरिजम को जोड़ा जायेगा. इसमें विभागीय स्तर पर युवाओं को जोड़ने के लिए काम करेगा.

> ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभाग के स्तर से कई काम शुरू किया गया है. गांव के खान-पान से पर्यटक जुड़ेंगे और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.
>
> **नारायण प्रसाद**, पर्यटन विभाग.

सौजन्य से प्रभात खबर | पटना | 06.07.2022 | पृष्ठ सं० 01

उद्यमिता पर बिहार की बेटी आर्या की किताब बनी देशभर के लिए मॉडल

गर्व

■ अनामिका

मुजफ्फरपुर। गया (बिहार) के बाराचट्टी प्रखंड में अधिकतर लोगों के लिए दूसरे शहर जाकर दिहाड़ी करना या फिर अपने खेत में काम करना ही रोजगार था। अपना उद्यम शुरू करना है, यह सोच अगर आती भी तो सभी एक ही तरह के काम में लग जाते। रानी नाम की महिला जिसके पति कोविड की वजह से वापस आए तो कोई काम नहीं था। ऐसे में उस महिला ने एक दुकान खोली जहां दिन में शृंगार और किराने का सामान मिलता और शाम में चाय-पकौड़ी बनाती। रानी ने इस काम को शुरू करने से पहले एक पूरा प्लान बनाया। कितनी पूंजी लगेगी, कितना कैपिटल बना कर रखना है। कैसे ग्राहकों से बात करनी है। दुकान चलने लगी तो पति भी बाहर नहीं जाकर उसी में सहयोग करने लगे। इसी तरह राजस्थान में तारानगर ब्लॉक में हिमानी ने उद्यम शुरू करने की जब सोची तो पहले हुनर को पहचान उसे ट्रेनिंग दी गई। आज चूड़ी के सबसे बड़े निर्माता के रूप में उसकी पहचान है। अलग-अलग राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता के विकास और उनकी रूकावटों से लेकर उसके समाधान की राह दिखाती ऐसी कितनी ही कहानियों के साथ जिले की बेटी की किताब फील्ड फैसिलेटर गाइड आज पूरे देश के लिए मॉडल बन गई है।

ग्रामीण उद्यमिता पर मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मोयेत्री की पुस्तक ह्यफील्ड फैसिलेटर गाइडह्न के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। महिला और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने, रुकावटें, हल आदि पर यह किताब राह दिखाती है। 15 राज्यों में शोध के बाद डेढ़ साल में यह पुस्तक पूरी हुई है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसे लॉन्च किया है। मंत्रालय इसमें सुझाए तरीकों के आधार पर योजना बनाने की पहल करेगा।

- पुस्तक 'फील्ड फैसिलेटर गाइड' के अनुसार कार्य करेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय
- महिला और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने, रुकावटें, हल आदि पर राह दिखाती है किताब
- 15 राज्यों में शोध के बाद डेढ़ साल में पूरी हुई पुस्तक, ग्रामीण विकास विभाग ने किया लॉन्च

ग्रामीण उद्यमिता में ये हैं तीन मुख्य रुकावटें

- एक ही तरह की चीजें या काम को करना, ऐसे में उद्यम नहीं चलता और फ्लॉप हो जाता है
- प्रतियोगिता के बीच मार्केटिंग, कॉस्ट की चुनौती
- आइडिया के बाद फाइनेंस कैसे लाएं

उद्यमियों को राह दिखाती पुस्तक

कलमबाग चौक निवासी स्वर्गीय राजेश कुमार वर्मा और निशी वर्मा की बेटी आर्या बताती हैं कि नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन कुटुम्ब श्री के साथ मिलकर हमने इस पर काम शुरू किया। अलग-अलग राज्यों में ग्रामीण उद्यमिता को लेकर एक ही तरह की चुनौती है। खासकर महिलाएं जो पहली बार किसी तरह के उद्यम से जुड़ रही हैं। हमने इसी पर फोकस किया है। जो रूकावटें हैं उन्हें दिखाते हुए, उसे दूर कैसे किया जा सकता है, यह इन महिलाओं की कहानी के जरिए ही दिखाया गया है। कहां -कहां से मदद मिल सकती है, ये सारी चीजें इस किताब में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी चरणजीत सिंह ने इस किताब को ग्रामीण उद्यमिता को नई दिशा देने वाला बताया है।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 06.07.2022 | पृष्ठ सं० 04

सर्वाधिक पेसमेकर लगानेवाले संस्थानों में शुमार हुआ आईजीआईसी

पटना, प्रधान संवाददाता। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आईजीआईसी), पटना देश में सर्वाधिक पेसमेकर लगानेवाले संस्थानों में से एक हो गया है। यहां पिछले एक वर्ष में 1008 हृदय रोगियों में पेसमेकर लगाया गया। कोलकाता मेडिकल कॉलेज के बाद यह पूरे देश में दूसरा सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है।

कोलकाता के संस्थान में यह पेसमेकर निःशुल्क लगाया जाता है। इस कारण वहां दो हजार से ज्यादा पेसमेकर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। आईजीआईसी में एक लाख से डेढ़ लाख रुपये पेसमेकर लगाने के लिए लगता है। अस्पताल निदेशक डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि ज्यादातर मरीजों को आयुष्मान भारत योजना अथवा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से पेसमेकर लगाने का काम होता है। बताया कि प्रतिवर्ष लगभग 1700 से 1800 पेसमेकर और एंजियोप्लास्टी लगाया जाता है। दावा किया कि यह सरकारी संस्थानों में देश की सर्वाधिक संख्या है।

क्यों बढ़ रही हृदय रोगियों की संख्या : संस्थान के निदेशक डॉ. सुनील कुमार और डॉ. संदीप कुमार ने बताया कि आईजीआईसी के ओपीडी में प्रतिदिन 300 से 350 मरीज आते हैं। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति पहले की तुलना में जागरूकता भी बढ़ी है। पहले लोग छाती, पीठ अथवा कंधे में दर्द को गैस का दर्द समझकर नजरअंदाज करते थे। लेकिन अब लोग जांच कराने अपने नजदीकी अस्पताल अथवा संस्थान में जरूर जाते हैं। जांच में इनमें से कई लोग हृदय रोग से पीड़ित पाए जाते हैं। समय पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होने अथवा पेसमेकर लगने से उनकी जान बचाने में मदद मिलती है। कहा कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, मोटापा, हाई बीपी और डायबिटीज के साथ ही निष्क्रिय जीवनशैली से भी पिछले कुछ सालों में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ी है। निदेशक ने बताया कि आईजीआईसी के इमरजेंसी में भी मरीजों से संबंधित सुविधाओं का विसतार हुआ है। इस कारण अब रात में भी हृदयाघात से पीड़ित मरीज पहुंचने लगे हैं। इमरजेंसी में 24 घंटे पैथोलॉजी जांच, ईसीजी, ईको आदि की सुविधा मरीजों को मिल रही है।

1008
पेसमेकर एक साल में लगाए गए और 511 लोगों की हुई एंजियोग्राफी

गंभीर हृदय रोगियों में लगाया जाता है पेसमेकर

आईजीआईसी के सहायक निदेशक डॉ. संदीप कुमार ने बताया कि गंभीर हृदयरोगियों में पेसमेकर लगाया जाता है। जबकि हल्का ब्लॉकेज होने पर एंजियोप्लासटी कर स्टेंट लगाने का कार्य होता है। सहायक निदेशक डॉ. रोहित ने बताया कि राज्यभर में सर्वाधिक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लासटी लगाने का काम भी आईजीआईसी में ही होता है। यहां पिछेल वर्ष कुल 2054 लोगों की एंजियोग्राफी की गई। उनमें से 51 लोगों में स्टेंट लगाया गया। पेसमेकर और स्टेंट लगाने में डॉ. संदीप और डॉ. रोहित के अलावा डॉ. अनूप सिंह, डॉ. नसर और डॉ. नीतिश रंजन जैसे अनुभवी डॉक्टरों की टीम भी यहां मौजूद है। डॉ. संदीप ने कहा कि नए भवन में कई अतयशधुनिक उपकरणों के लगने के बाद पेसमेकर और एंजियोप्लास्टी की संख्या और बढ़ सकती है।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 06.07.2022 | पृष्ठ सं० 6

बिहार कोविड अपडेट

⇒ कुल सक्रिय मामलों की संख्या	1269
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान नए पॉज़िटिव मामलों की संख्या	338
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या	238
⇒ कुल वैक्सीनेशन	13,71,96,668
⇒ कम से कम एक डोस	7,14,09,418
⇒ पूर्ण वैक्सीनेटेड	6,20,84,222

बिहार फाउन्डेशन नेटवर्क

विदेश अवस्थित चैप्टर

कतर
दक्षिण कोरिया
जापान
हॉग कॉग
यू.ए.ई.
सिंगापुर
बहरीन
न्यूजीलैंड
कनाडा
यू.एस.ए.
ऑस्ट्रेलिया
सऊदी अरब

देश अवस्थित चैप्टर

मुम्बई
हैदराबाद
पुणे
चेन्नई
नागपुर
गुजरात
कोलकाता
वाराणसी
गोवा

पाठकों से अपील

बिहार फाउन्डेशन के जुड़ने के लिए

बिहार फाउंडेशन उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक निबंधित सोसाईटी है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बाहर बसे देश-विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है। वर्तमान मे बिहार फाउंडेशन के कुल 21 चैप्टर्स हैं. बिहार फाउंडेशन से जुड़ने के लिए नीचे दिए वेबसाइट पर जाकर Non Resident Bihari Registration पर क्लिक करें और उपलब्ध फार्म को भरकर जमा करें -

https://biharfoundation.bihar.gov.in.